agricultural sector could not create enough employment opportunities for the growing rural population. The draft sixth plan document states that the number of economically weak has increased.

(b) Apart from the investment in the public sector and private sector of the economy which to varying extent benefits the poorer sections in the rural areas, Government have the following specific Programmes which are aimed at improving the living conditions of the rural poor:—

(1) *Integrated Rural Development Programme*

This programme is aimed at raising the families of the rural poor above the poverty line by providing them income-generating assets and self employment through a combination of subsidies provided by the State and loans provided by the banking institutions. The programme is now being implemented in 2,600 blocks out of the total of 5,000 blocks in the country and 300—400 poor families are directly assisted under this programme in each block every year.

(2) *Small Farmers & Marginal Farmers Development Agency.*

169 agencies, covering 201 districts and 1818 blocks, are now in operation and these agencies are providing subsidies and arranging loans for small and marginal farmers and agricultural labourers. Since the inception of the programme 77.13 lakhs participants have been actually assisted and 165.17 lakhs participants have been identified for providing assistance.

(3) *Food for Work Programme*

The programme was launched in 1977 with the purpose of providing assistance exclusively to the rural poor through employment 3,803 million tonnes of foodgrains have been provided by way of wages to the rural poor who have been employed under the scheme and it is estimated that 428.22 million mandadays of employment had been generated by this programme in 1977-78 and 1978-79. The programme is being continued in the current year also.

(4) *Drought Prone Areas Programme*

A programme for improving environmental conditions in chronically drought prone areas with the objective of stabilising and improving the incomes of the poorer sections of the population in such areas is under operation in 74 districts covering 13 states. The programme extends to 1/5th of the area of the country and 12 per cent of the population. The programme is being continued in the Sixth Plan also.

(5) *Command Area Development Programme*

This was started with the intention of utilising the potential generated by irrigation projects and the benefits of this programme accrued substantially to the rural poor through additional employment opportunities and land development etc. 42 Command Area authorities are in operation and this programme is aiso an on-going programme.

(6) *Training for self-employment scheme*

Started in the current year, the scheme is intended to benefit unemployed young men and women in the rural areas. The target is to train on an average, at least 40 young men and women in each block in the current year in taking up schemes for self-employment. The scheme extends to the whole country and at the completion of training, the beneficiaries to be provided subsidies and loans for starting enterprises of their own.

ग्वालियर (मध्य प्रदेश) से दिल्ली और भोपाल के लिए एस० टी० डी० सेवा

22 **श्री एन० के० शजबलकर** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर (मध्य प्रदेश) से दिल्ली और भोपाल के लिए एस० टी० डी० सेवा कब शुरू होगी

और सकी व्यवस्था में हो र इस अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण है ;

(ख) क्या ग्वालियर से दिल्ली और भोपाल तक की टेलीफोन लाइनें सदैव खराब रहती हैं और यदि हां, तो इसके कारण क्या है; और

(ग) दिसम्बर 1979 में कुल कितने दिन और इन दिनों में कितने-कितने समय के लिए लाइनें खराब रहीं ?

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) ग्वालियर से दिल्ली और भोपाल के लिए एस० टी० डी० सेवा क्रमशः वर्ष 1980 के मध्य तथा अन्त तक आरम्भ कर दी जायेगी। इन मार्गों में एस० टी० डी० सेवा चालू करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि सम्बन्धित स्टेशनों को जोड़ने वाले उपयुक्त रेडियो उपस्कर समय पर उपलब्ध न हो सके ।

(ख) जी, । नहीं ।

(ग) दिसम्बर 1979 के दौरान मार्ग में आउटलेट उपलब्ध न होने के कारण कितने दिन लाइनें बन्द पड़ी रहीं उनकी संख्या :—

3 दिन—ग्वालियर—भोपाल मार्ग पर

8 दिन—ग्वालियर—नई दिल्ली मार्ग पर

आउटलेट उपलब्ध न होने के कारण हुए अवरोध की अवधि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है ।

विवरण

(वह अवधि जिसमें सभी सर्किटों में अवरोध उत्पन्न हुआ और मार्ग पर कोई आउटलेट उपलब्ध नहीं था ।)

(क) ग्वालियर से भोपाल मार्ग पर—(कुल सर्किट—5)

तारीख	आउटलेट उपलब्ध न होने की अवधि
	घण्टा-मिनट
1-12-79 . .	02.00
20-12-79 . .	06.45
21-12-79	10.30

(ख) ग्वालियर से नई दिल्ली मार्ग पर- - (कुल सर्किट- - 4)

तारीख	आउटलेट उपलब्ध न होने की अवधि
	घण्टा-मिनट
2-12-79 . .	10.15
5-12-79 . .	1.45
9-12-79 . .	0.15
12-12-79 . .	0.15
16-12-79 . .	1.15
20-12-79 . .	8.30
25-12-79 . .	11.30
26-12-79 . .	13.00

मध्य प्रदेश को डीजल और मिट्टी के तेल का आवंटन

23. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर और दिसम्बर, 1979 के दौरान मध्य प्रदेश को, विशेष कर ग्वालियर जिले को डीजल और मिट्टी के तेल का कितना प्रति व्यक्ति कोटा आवंटित किया गया और उत्तर प्रदेश को आवंटित कोटे से यह कितना कम था और मध्य प्रदेश को इन वस्तुओं का कम कोटा आवंटित करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल की सप्लाई का कोई विशेष प्रबन्ध करने का है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मिट्टी के तेल की सप्लाई के मामले में मध्यम आर्थ वर्ग के लोगों और गरीब श्रमिकों को ऐसी ही प्राथमिकता दी जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : डीजल और मिट्टी के तेल के प्रति व्यक्ति आवंटन के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है । इस विषय में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) संघ शासित प्रदेशों और राज्यों को पेट्रोलियम विभाग द्वारा डीजल का मासिक आवंटन किया